

मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या कम करना

(ग) जी नहीं ।

2428. श्री नत्ताब सिंह चौहान :
श्री वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और
सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे
कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के दो
सचिवों के स्थान पर इस : मय केवल एक
सचिव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण
हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार संयुक्त
सचिव, उप-सचिव, आदि जैसे पदों की संख्या
में भी कमी करने का है ;

(घ) क्या उनके मंत्रालय और उससे
सम्बद्ध स्थायित्त निगमों में कर्मचारियों की
संख्या कार्य के लिहाज से बहुत अधिक है ;
और

(ङ) इस बारे में सरकार का कब तक
मितव्ययता करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और
सहकारिता मंत्री (श्री मोहन चारिया) :

(क) तथा (ख) . जून, 1977 से पहले
वाणिज्य मंत्रालय में तीन सचिव थे, अर्थात्
सचिव (वाणिज्य), सचिव (विदेश व्यापार)
तथा सचिव (वस्त्र) तब से कार्य का बेहतर
समन्वय सुनिश्चित करने तथा मितव्ययिता
की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए
मंत्रालय का पुनर्गठन किया गया है । इस
समय केवल दो सचिव हैं अर्थात् वाणिज्य
सचिव, जो निर्यात उत्पादन तथा विदेशी
व्यापार का कार्य देखते हैं और सचिव
(वस्त्र) जो वस्त्र से सम्बन्धित सारा कार्य
देखते हैं जिसमें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र,
मानव-निर्मित रेशे तथा पटसन वस्त्र शामिल
हैं । वे हस्तशिल्प से सम्बन्धित कार्य को
भी देखते हैं ।

(घ) तथा (ङ). मंत्रालय तथा
इसके स्वायत्तशासी निगमों के कार्य भार की
अवधिक समीक्षा कार्य अध्ययन यूनिट द्वारा
की जाती है । कार्य अध्ययन ग्रुप की अंतिम
रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय में
कर्मचारियों की संख्या कार्यभार की तुलना में
अधिक नहीं है । मितव्ययिता की दृष्टि
से वे समीक्षाएं समय-समय पर की जाती
रहेंगी तथा तदनुसार स्टाफ की संख्या को
समायोजित किया जायेगा ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों
का खोला जाना

2429. श्री नत्ताब सिंह चौहान : क्या
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने
की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली
स्थित भारतीय पर्यटन विकास निगम के
होटलों से कुल कितनी वार्षिक आय हुई ?

(ख) क्या निगम का विचार पर्वतीय
नगरों में और उत्तर प्रदेश के आगरा,
इलाहाबाद और वाराणसी के पर्यटन केन्द्रों
में होटन खोलने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य
वार्ते क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री
(श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत
पर्यटन विकास निगम दिल्ली में 6 होटलों
का संचालन कर रहा है । 1974-75,
1975-76 तथा 1976-77 के दौरान
इन होटलों की कुल वार्षिक वित्तीय क्रमशः
832.08 लाख, 924.95 लाख तथा
1081.43 लाख रुपए (अंतिम)
भी ।

(ख) और (ग). निगम की इलाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी नगरों में होटल खोलने की फिनाइल कोई योजनाएँ नहीं है। निगम का आगरा में एक 100 कमरों वाले स्वागतकेन्द्र-ब-होटल के निर्माण का प्रस्ताव है, परन्तु वित्तीय साधनों की कमी तथा गणराश-मिकताओं के कारण, इस परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वाराणसी में निगम पहले ही एक 50 कमरों वाला होटल सितम्बर 1973 में चला रहा है।

Issue of Import Licences by Faridabad Office of Import Trade Control

2430 SHRIMATI MRINAL GORE.
Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether some additional import licences were issued by the Faridabad Office of the Import Trade Control in favour of some parties under public notice No. 140/70 dated the 11th September, 1970 for the item Tin Plate or Tin Plate w/w even though that item was not a permissible item under the said public notice;

(b) if so, who were the beneficiaries of such licences and what was the value of each licence;

(c) whether any action was taken against the Officials;

(d) whether any prosecution was launched against them; and

(e) whether any adjustment was made against parties' regular licences?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) Import of tin plate waste was allowed in a few cases because of a bona-fide mistake by the

Faridabad office as the item was not specifically mentioned as non-permissible in the public notice. Decision to disallow it was taken subsequently.

(b)

1. M/s. Aarao Engineering Works, Ludhiana	3,63,995
2. M/s. Jiwan Engineering Works Ludhiana.	26,89,427
3. M/s. Zieco Engineering Works, Ludhiana	2,29,292
4. M/s. T.C. Industries, Ludhiana	16,51,675

Tin Plate Waste was one of the 10-12 steel items allowed under these licences.

(c) No, Sir.

(d) No, Sir.

(e) Yes, Sir. In two cases complete adjustments have been made and in the remaining two cases partial adjustments have been made. In the latter two cases, adjustments will be completed when the parties come up for further licensing.

Asian Cable Company

2431. SHRI JYOTIRMOY BOSU:
Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether Asian Cable Company was involved in serious black marketing of imported items worth market value of about a crore and a half of rupees;

(b) if so, what precise steps have so far been taken against actual owners and culprits who are the beneficiaries of this black marketing;